sactory to all the States so that there would be no cause for grievance whatsource and the Centre would not be blumed for what happens in the States

Mr. Speaker: That has no bearing on the main question

भी जगनाथ राव जोशी : प्रजातन्त्र केवल कोरे सिद्धान्तों के भरोसे नहीं चल सकता है। भगर प्रजातन्त्र के मिद्धान्तों को कार्यान्वित करके बन्छी ग्रीर स्वस्थ परम्पराये स्वापित की जायें. तभी प्रजातन्त्र चल सकता है। इस सम्बन्ध में अधिकारास्ट पक्ष की विशेष विम्मेदारी है। इसी मदन मे 7 नवम्बर, **भी दुर्घटना** को लेकर राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ भीर जनसभ के खिलाफ कुछ खास इल्जाम लगाए गए थे। बाद मे जाच से यह पता चला कि उस दुर्षटना में इन दानो दलो का कोई हाय नहीं या। तो क्या मन्त्री महोदय का यह कर्तव्य भीर दायित्व नहीं है कि वह प्रथने मन की भावना को प्रवाट करके क्षमा-वाचना करे और इस सदन को बताये कि मैंने जो धारोप लगाया था, वह ठीक नही था<sup>?</sup>

Shri Y. B. Chavan: No, I cannot make that statement.

वैदेशिक तेल कम्पनियों में छंटनी

\* 1235 भी हुकम चन्द कछवाय :

भी जगन्नाय राव जोशी :

श्री जनादंतन :

भी वासुदेवन नायरः

नया श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि .

- (क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों में खुट शो के बारे में जाच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने नर्भा विदेशी तेल कम्पनियों के बारे में जाच कर ली है,
- (ख) यदि हा तो उसका व्योरा क्या है, श्रीर

(ग) वदि नहीं, तो इसके द्वारा अवता प्रतिबेदन प्रस्तुत करने में कितना समय सबर्वे की सम्मावना है ?

सन तथा पुनर्वात नंत्री (थीं हावीं): (क) धीर(ख) यह आयोग 4 जून, 1967 ही को स्थापित किया गया। धाशा है कि बह अपना कार्य बीझ ही धारम्भ कर देगा।

(ग) इस धायोग को धपनी रिपोर्ट छ महीने के धन्दर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

भी हुकम यन्त्र कछनाय: स्पा सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि गुजरात भीर गौहाटी में जो नई कम्पनिया बन रही हैं, उनमें इन विदेशी तेल कम्पनियों से छोटे जाने वाले कर्मचारियों को काम दिलाबा जाये?

भी हाथीं : वे सरकार की कम्मिनियां तो नहीं है, लेकिन रिट्रचमेंट में जो लोग फ़ासतू करार दिये जायेगे, उन को दूसरी जगह रखने के लिये कम्मिनियों को जरूर कहा जायेगा।

शं: हुन्म चन्द कखवाय : माननीय मन्ती ने बताया है कि 6 महीने में रिपोर्ट शायेगी, जाच चल रही है। रिपोर्ट भाने के बाद उसे कार्य मे लाने के लिये कितना समय लगेगा ?

भी हार्यः जितना कम समय लगे, उतनाः

भी उपलाग राव जोशी कोटी की जो टर्म्ज भाफ रेफोर बनी हैं, उसमें छटनी न हो, इस दिट से जा मजदूर है उनको भपने कामों के बारे में काई भाष्यस्ती यानी गारन्टी मिले, क्या इस बात का बोई सुझाव भ्राया है ?

श्री हार्ष: ऐसा सुझाव बाबा है। केकिन गारल्टी के बारे मे बायल कम्पनीज ने कहा है कि वे लोग वालन्ट्री रिट्रेन्चमेट नहीं करेंचे, लेकिन जहा कोई जगह सरप्लस हो, वह उन्ह क्ष्मानक को केवन की नंभूरी उन को दी कानी चाहित। मेकिन हमारे वर्कन ने इस वात को नहीं माना।

Shri Vasudovan Nair: The employees have already made it known that the terms of reference are not proper and they have objections to them. In view of this, would Government discuss this matter again with representatives of the workers and revise the terms of reference? Also, what is going to happen till the Commission goes into it and comes to a decision? Till that time, is there a guarantee that there will be no retrenchment?

Shri Hatal: So far as the terms of reference are concerned, one of the MPs. Shri Mohammad Ismail, did see me day before yesterday. I told him that if it is found that the terms of reference will not serve the object we have in view, we could discuss the matter If it is found that those terms are not likely to have the results in view, we shall certainly discuss them and reconsider the matter.

So far as the surplus staff is concerned, I have had discussions with the works and management also. The Caltex people had come to me They said they are prepared to take 24 people immediately there are vacancies in Calcutta.

Mr. Speaker: Next question.

Shri Ganesh Ghosh: We have one or two more questions to ask.

Mr. Speaker: We are already very late.

Report on Science Policy

\*1236. Shri Tridib Kumar Chandhuri: Shri S. C. Samanta: Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of Education be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Chairman of the University Greats of India; and

Commission has poposed that a report on Science Policy be placed annually before Parliament;

- (b) whether the Council of Scientific and Industrial Research would propare this special report; and
- (c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Rhagwat Jha Azad):
(a) Dr D S. Kothari, Chairman, University Grants Commission while delivering a lecture on April 26, 1967, at Sapru House, New Delhi, made a suggestion, in his personal capacity, that an annual report should be placed before Parliament dealing with the progress of Science and matters having a bearing on Science Policy.

(b) and (c). There is no proposal for preparation of such a report by the Council of Scientific and Industrial Research The Scientific Advisory Committee to the Cabinet has been giving thought to the publication of an annual report on the implementation of the Scientific Policy Resolution, and also on the possibility of making this report public

Shri S. C. Samanta: May I know which department of his Ministry is dealing with the International Council of Scientific Unions and Associations, and whether that department will be able and fit to put in a report?

Shri Bhagwat Jha Azad: In this case, before this the Estimates Committee of Parliament had recommended such an action. As it is known that the Scientific Committee of the Cabinet is considering this question and has decided that it will review the scientific policy of the country and prepare a report and submit it to Government, it can be later on considered for publication also.

श्री बक्तपाल लिह: मैं यह जानना चाहता है कि हमारे देश में न गर्थ-न्वेक पर रिक्षर्य